मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता ।

दुनियां के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है ।

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 50 | अगस्त 1992 | 50 पैसे

धन्धा गोमाँस का

मोनोपाली हिन्दूओं की

धन्धे और धर्म का निकट का रिश्ता रहा है। आमतौर पर धन्धे की जरूरत के मुताबिक धर्म अपने चोले बदलते रहे हैं। राम मन्दिर की नौटंकी इसी सिलसिले की कड़ी है। पर आइये एक अन्य प्रहसन पर निगाह डालें।

गोमांस का भारत से हर साल निर्यात हजार करोड़ रूपयों के आँकड़ों में होता है। केन्द्र सरकार की गोमांस के धन्धे में अच्छी-खासी भूमिका है। १९८९ से गाजियाबाद से ही फैक्ट्रियों में परिष्कृत-रिफाइन करके केन्द्र सरकार हर साल ६०० करोड़ रूपये मूल्य का गोमांस अन्य देशों को भेज रही है।

यहां गोमांस के धन्धे में मारजिन बहुत है। ऊल-जलूल कानून इस धन्धे में आड़े आते हैं पर कानूनों की भूल-भुलैया से पार पाने के लिये साहबों-नेताओं को खुश रखना गोमांस का धन्धा करने वालों के लिये आसान काम है। फिर भी, अन्य कारणों से जब-तब कुछ लफड़ा हो ही जाता है।

राम नाम के जाल में फँसे उत्तर प्रदेश के जनता दल मन्त्रि-मण्डल के समय का वाकया है। अपना हिन्दूपन दिखाने के लिये मुख्यमन्त्री मुलायम सिंह ने गऊमाता का दामन पकड़ा। यूं भी, गोपाला वंश का खून उनकी रगों में दौड़ रहा था। पवित्र नगरी बनारस की राह हो रहे सात सौ करोड़ रुपये सालाना के गोमांस के प्रायवेट धन्धे के खिलाफ मुख्यमन्त्री मुलायम सिंह ने छापे मारने का आदेश दिया। पर हाथ, पवित्र मथुरा के जनता दल विधायक सरदार सिंह गोमांस के प्रायवेट धन्धे के प्रमुख अभियुक्तों में! और ... और गाजियाबाद से भेजे गोमांस के दो ट्रक पुलिस ने पकड़े तो मन्त्रिमण्डल के सदस्य व गोपाला वंश के दूसरे सितारे डी. पी. यादव का नाम उभरा. उन छापों का राम नाम सत हो गया।

राम धुन पर सवार हो कर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां अपने खिसकते हिन्दू आधार को सम्भालने के लिये गऊमाता की पूंछ पकड़ी पर जब बात बनी नहीं तब मन्दिर का ड्रामा पुन: किया। खैर, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी मन्त्रिमण्डल के उस गोवंश बचाओ अभियान की भी एक झलक देखिये।

पिछले साल उत्तर-प्रदेश हो कर ४१५ 'पशु स्पेशल' गुजरी। कलकत्ता में कटने के लिये गाय-बैल-बछड़ों से भरी यह रेलें बेशक "प्रायवेट" माल ले जाती हैं पर रेलवे केन्द्र सरकार का महकमा है इसलिये उत्तर-प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी मन्त्रिमण्डल इस मामले में चुप रहा। मुख्यमन्त्री कल्याण सिंह ने आँखें सड़क पर गड़ाई और पवित्र बनारस नगरी फोकस में आई। गोमांस के धन्धे से जुड़े होने के आरोप में बनारस से एम पी रहे चन्द्रशेखर सिंह के खिलाफ सात केस दर्ज किये गये—

> गोमांस का धन्धा करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी मन्त्रिमण्डल की पहल पर पकड़े गये इन लोगों में अस्सी प्रतिशत हिन्दू हैं।

जनाब विरोधी पार्टी के थे, चलो अच्छा ही हुआ। बनारस के एक प्रभावशाली जमींदार बिजय सिंह का खजूरा मेला जिसमें जानवर इकट्ठे किये जाते थे वह बन्द हो गया। इससे क्षेत्र की बीस ट्रान्सपोर्ट कम्पनियाँ बन्द हो गई - बड़े लक्ष्य के लिये छोटी कुर्बानियाँ तो देनी ही पड़ती हैं। बात आगे बढ़ी। गोमांस के धन्धे से जुड़े लोगों पर उत्तर प्रदेश में छापे बढ़े। इस वर्ष जनवरी - जून के बीच ८५० लोग गिरफ्तार किये गये - इस वर्ष २५ मई से १८ जून के बीच लखनऊ हाइवे पर मारे गये छापों के दौरान ७७८ गाय-बैल-बछड़ों से लदे ३० ट्रक पुलिस ने पकड़े और ४३ मामले दर्ज किये। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में पुलिस को सभी अभि-युक्तों को छोड़ना पड़ा। इन छापों का भी राम नाम सत हो गया। [सामग्री हमने ३१ जुलाई ९२ की इन्डिया टुडे में श्री दिलीप अवस्थी के लेख से ली है।] पुन: मन्दिर नौटंकी का एक यह भी कारण था। खैर।

इस सिलसिले में आइये अन्त में विजनेस इन्डिया (८-२१ जून ९२) की एक रिपोर्ट को देखें। फोर्ड और एस्कोर्टस ट्रैक्टरों की निर्माता कम्पनी के चेयरमैन हर परशाद नन्दा की मान्यता है कि बैलों से जुताई के दिन अब खत्म हो गये हैं। मांस उत्पादन के लिये अधिक बैल उपलब्ध होंगे इसलिये श्री हर प्रशाद नन्दा गोमांस की फैक्ट्री लगाने की योजना गंभीरता से बना रहे हैं। एस्कोर्टस चेयरमैन के मुताबिक गोमाँस के निर्यात में उच्च मुनाफा हैं क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ गोमांस के भाव अन्य जानवरों के माँस से कम हैं। एस्कोर्टस कम्पनी ने केन्द्र सरकार की नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च से अपनी गोमाँस फैक्ट्री योजना के मुनाफे के सम्बन्ध में अध्ययन करने का आग्रह किया है। स्वराज पाल के एस्कोर्टस पर कब्जे के प्रयास के नाकाम होने पर हर परशाद नन्दा कुछ अधिक ही धार्मिक हो गये थे। शराब निर्माण में शोहरत वाले मोहन के साथ एस्कोर्टस चेयरमैन हर परशाद नन्दा ने जागरण का सिलसिला शुरू किया। जागरण और .. और गोमाँस की फैक्ट्री! खैर, यह क्या कम है कि हजारों करोड़ रूपये में छलाँग की सम्भावना वाले गोमाँस के धन्धे में हिन्दू मोनोपाली को मजबूत करने के लिये श्री हर परशाद नन्दा कदम उठा रहे हैं।

अरबों-खरबों रूपयों का मामला है इसलिये आने वाले दिनों में गोमांस खाने को वेद सम्मत सिद्ध करने के लिये हर परशाद सरीखे लोगों की तरफ से शास्त्रार्थ करने धर्माधिकारी अखाड़े में उतरेंगे। अतिथि सरकार के लिये गोमांस परोसने वाली महाभारत की कहानी के रेडियो-टी वी पर आने की सम्भावना है। देश हित में गोमांस एक्सपोर्ट की बात का तो नारे का रूप लेने की सम्भावना है। यह सब बढ़िया है। इस वाकये से यहाँ कुन्द पड़ी समझ को कुरेदने-परखने-आलोचनात्मक ढँग से मामलों को देखने वाली कुछ धार मिल सकी तो बहुत बढ़िया होगा! गोमांस रूप में गोधन का यहाँ प्रचलन एक आहूति तो होगी ही, यह एक प्रायश्चित भी होगा। तथास्तु।

नोट—विषय के नाजुक होने के सन्दर्भ में ही हिन्दू शब्द का इस्तेमाल किया हैं। इसे अन्यथा नहीं लें।

एक फ़ैक्ट्री मजदूर की कलम से

यूनियन चुनाव

क्या हम वोट इसलिये देते हैं कि हमारे वोटों से बने लीडर मशीन पर काम नहीं करें? घर बैठ कर भी "लीडर अलाउन्स" लें? कैन्टीन में मुफ्त में बढ़िया खायें और ठेकेदार से रिश्वत लें? चन्दा तो खायें ही, कमीशन से मुटियायें? कपड़े भी नहीं बदलें? हमारे बीच न बैठ कर साहबों की केबिनों में बैठें? हमारे सिर पर बैठें? एग्रीमेंटें हम पर जबरन थोपें? हममें से कोई इनके कारनामों का विरोध करे तो उसे धमकायें, उसके साथ मार-पीट करें, उसे सस्पैन्ड करायें? अपने हित में हम जब कभी सामुहिक कदम उठाते हैं तब हमारा विरोध करें? मैनेजमेंट की पैरवी करें? लोकल-पूरबिया-जाट - गूजर- चमार पण्डत-फस्ट प्लान्ट-थर्ड प्लान्ट के तीर चला कर फूट डालें? क्या हम लीडर इसलिये चुनते हैं कि हम मात्र चन्दा देते रहें और लीडर हमारे काम करते रहें? हम घर से ड्यूटी और ड्यूटी से घर की भागमभाग को छोड़ कर बाकी मामलों में निष्क्रिय बने रहें? लीडर खुद बेशक खायें पर थोड़ा हमें भी दिलायें? सोचिये, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। लीडरों को गाली दे कर हम बरी नहीं हो जाते।

लीडरी के लिये खड़े लोग यूनियन चुनाव के वक्त कितने बेचैन होते हैं। कितनी चिन्ता होती है उन्हें मजदूरों की भलाई की। मजदूरों की पव्वों-बोतलों से सेवा करने, पैसे खर्च करने, भाग-दौड़ करने में यूनियन चुनाव के समय लीडर बनने के इच्छुक दिन-रात एक करते हैं—घर में भी चैन से नहीं बैठने देते। बहुत उतावले होते हैं यह लोग उस भार को ढोने के लिये जो उनके कन्धों पर पड़ने जा रहा है। क्यों-क्यों? चुनाव के समय हममें दिन-रात अनुनय-विनय करने वालों को चुनाव के बाद हमसे मिलने की फुर्सत क्यों नहीं मिलती?

हम बार-बार के चुनावों से देख चुके हैं कि जिन्हें भी हम चुनते हैं वे ही मैनेजमेंट से मिल जाते हैं बिक जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह निकालें कि धोखा खाते आये हैं चलो एक बार और सही? कोई न कोई लीडर तो बनेंगे ही - किसी न किसी को वोट तो देनी ही पड़ेगी - कुये या खाई में एक को चुनना ही पड़ेगा जैसी दलीलों में कोई दम हैं क्या? नहीं, पर फिर भी इनकी आड़ में हम जाति-इलाके-डिपार्टमेंट जैसी अपने भ्रम की बेड़ियों से रस भरने की उम्मीद करते हैं?

क्या कोई हमें कुछ दिला सकता है? कुछ दिलाने की ताकत लीडर बनने के बाद ही किसी में आती है क्या? और अगर आती है तो क्यों? चन्दे से ही सन्तुष्ट हो कर हमारी समस्यायें हल करने के लिये कोई लीडर बनता है क्या? लीडर खुद खायें पर हमें भी कुछ दिलायें, आटे में नमक के बराबर तो दिलायें ही वाली हमारी सोच बिचौलिये पैदा करने में योगदान नहीं देती क्या? अपने हित में हमें बहुत से सवालों पर सोचना होगा।

यह कुछ बातें झलानी ट्रस्ट उर्फ गेडोर में यूनियन चुनाव की इस समय मची धमाचौकड़ी में उठी हैं। कुछ दिन पहले एस्कोर्टस में ऐसी ही स्थिति थी। और फिर केल्विनेटर हो चाहे हितकारी पोट्रीज, गुडइयर हो चाहे ईस्ट-इंडिया काटन, तन्त्र की बातें यही हैं। संगठन तो हमें चाहियें ही पर उपरोक्त तथ्यों को देखते हुये संगठन के नये स्वरूप के बारे में सोचिये।

— भू०

संपर्क — मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटाचौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद 121001

पद पर और रिटायर के बाद

फरीदाबाद में मैनेजमेंटों के खिलाफ मजदूरों की शिकायतों का आमतौर पर लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी स्वागत करते हैं क्योंकि मन्थली तो चुप रहने के लिये होती है, शिकायत को रफा-दफा करने के एक्सट्रा लगते हैं और शिकायत के वजन के मुताबिक गड्डी की साइज होती है। मैनेजमेंटों के साथ सौदे पटने तक आमतौर पर शिकायतकर्ता मजदूरों को भरोसा देना और फिर मजदूरों को थकाने के लिये मामलों को बहुत-बहुत लम्बा खींचना लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जनरल पालिसी है। आमतौर पर ट्रेड यूनियन लीडरों-वकीलों की इस सिलसिले में हिस्सा-पत्ती होती है और फरीदाबाद में वे खागड़ों की तरह खुले चर रहे हैं। एक ट्रेड यूनियन लीडर के मुताबिक इस समय फरीदाबाद में सब रंग-रूप के ट्रेड यूनियन लीडरों के लिये मजदूर ग्राहक हैं। खैर, यहाँ हम लेबर डिपार्टमेंट के एक रिटायर अधिकारी की कुछ चर्चा करेंगे। मामला बाटा फैक्ट्री से जुड़ा है।

फरीदाबाद में बाटा फैक्ट्री मैनेजमेन्ट ने कम्पनी के स्थाई आदेशों का खुला उल्लंघन किया। एक पीड़ित मजदूर ने स्टैन्डिंग आर्डरों का हवाला दे कर राहत की मांग की तो मैनेजमेन्ट ने उसे दुत्कार दिया और अदालत जाने को कहा। उस मजदूर ने लेबर डिपार्टमेन्ट में शिकायत डाली। सीधा-सरल मामला था, छोटा मामला था फिर भी मामले को लम्बा लटका कर रफा-दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन शिकायतकर्ता मजदूर के अड़े रहने ने मामला कुछ कम्पलीकेट कर दिया।

लेबर कमीश्नर रहे श्री धर्मेन्द्र नाथ के नाम से फरीदाबाद के काफी मजदूर परिचित हैं पर कम ही मजदूर जानते होंगे कि रिटायर होने के बाद यह श्रीमान बाटा मैनेजमेन्ट क लीगल एडवाइजर हैं। स्थाई आदेशों के उल्लघन की शिकायत करने वाले वरकर को फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान ३१ जुलाई को अधिकारियों ने बुलाया। केबिन में उसे रिटायर लेबर कमीश्नर धर्मेन्द्र नाथ, परसनल अफसर और यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मिले। श्री धर्मेन्द्र नाथ ने बाटा मैनेजमेन्ट के लीगल एडवाइजर के तौर पर बात की और शिकायतकर्ता मजदूर से लेबर डिपार्टमेन्ट से अपनी शिकायत वापस लेने को कहा। वरकर द्वारा आना-कानी करने पर रिटायर लेबर कमीश्नर ने धमकी दी कि मैनेजमेन्ट सुप्रीम कोर्ट तक जायेगी।

फरीदाबाद में तो लेबर डिपार्टमेन्ट के अधिकारी अपने वर्तमान और भविष्य के हितों को ध्यान में रख कर काम करते ही हैं, चन्डीगढ़ में रेफर होने गये केसों को थोक में रिजैक्ट किया जाना भी इसी सिलसिले की कड़ी लगती है ...।

बिचौलिये सर्वशक्तिमान ?

तेज-तर्रार मजदूरों का बिचौलिये बन जाना फरीदाबाद में एक सामान्य बात है। ऐसा क्यों होता है ? एक के बाद दूसरी फैक्ट्री और एक के बाद दूसरे व्यक्ति के ऐसे उदाहरणों का यहाँ अम्बार लगा है। फरीदाबाद में एक बढ़िया बात यह है कि यहाँ के अधिकतर बिचौलिये स्वयं मजदूर रहे हैं और किसी भी समय इसकी संख्या यहां हजारों में होती है। इससे व्यक्ति-विशेष की कमजोरियों का पहलू तो ऐसे घटनाक्रम के लिये गौण हो ही जाता है, इससे मजदूर माने विशेष गुण सम्पन्न होने की धारणा का थोथापन भी उजागर होता है। मजदूर आन्दोलन के लिये यह तथ्य महत्वपूर्ण है। खैर, यहां हम आटोपिन फैक्ट्री की हाल की एक घटना द्वारा सामने लाये अन्य पहलुओं की कुछ चर्चा करेंगे।

अपने बीच के तेज-तर्रार मजदूरों के बिचौलिये बन जाने ने मजदूरों के बीच खास किस्म के भय व भ्रमों को जन्म दिया है। मैनेजमेंट अथवा किसी नेता को सर्वशक्तिशाली मानने की तरह ही फरीदाबाद में मजदूर आमतौर पर अपनी फैक्ट्री के बिचौलियों को विशेष शक्ति से सम्पन्न, निजी अलौकिक शक्ति वाले मानते हैं। बिचौलियों को आम मजदूर कृष्ण और भीम के साथ थानेदार का मेल मानते हैं। उनकी समझ यह है कि बिचौलिये उर्फ लीडर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आम मजदूर सोचते हैं कि मैनेजमेंट को बिचौलिये नचा सकते हैं, कि वास्तव में फैक्ट्री का संचालन मैनेजमेंट नहीं करती बल्कि बिचौलिये करते हैं। मजदूरों की तकलीफों को बिचौलिये दूर नहीं करते इसका कारण बिचौलियों का लालच में आ जाना माना जाता है।

इस सबसे होता यह है कि मैनेजमेंटों और उनकी व्यवस्था (पूंजीवादी व्यवस्था) की बजाय बिचौलियों को आम मजदूर अपने दुख-दर्द का कारण मान लेते हैं। जबकि, फरीदाबाद में ही ढेरों उदाहरण आंखों के सामने हैं जो साफ-साफ दिखाते हैं कि मजदूरों को कन्ट्रोल करने के लिये बिचौलियों का मैनेजमेंट अन्य औजारों की तरह इस्तेमाल मात्र करती है। जब किसी मैनेजमेंट को लगता है कि कोई बिचौलिया यह करने लायक नहीं रहा है तब यह मैनेजमेंट उस बिचौलिये को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकती है। "मैनेजमेंट किसी की नहीं होती" की बात बार-बार की ऐसी घटनाओं से ही यहाँ चल निकली है और उस पर विचार करने की जरूरत है। आटोपिन की हाल की एक घटना से भी यही गूंज निकलती है।

इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित आटोपिन फैक्ट्री में सीटू बी एम एस-एच एम एस के बाद एल एम एस का झन्डा लगा कर आटोपिन मजदूरों में से उभरे बिचौलिये कुछ अधिक ही नँगई के साथ चर रहे थे। जोर-जबरदस्ती से वर्क लोड बढवाने का काम वे खुलेआम कर रहे थे। आम मजदूर तो मान ही रहे थे, बिचौलिये भी सोचने लगे कि फैक्ट्री वही चला रहे हैं। मजदूरों के प्रति बिचौलियों का जो व्यवहार था वह तो था ही, अधिकारियों के प्रति व्यवहार में भी वह झलक आने लगी। और इधर मजदूरों के प्रतिरोध को तोड़ चुकी मैनेजमेंट के लिये बिचौलिये फालतू हो गये, फालतू का सिरदर्द हो गये। कुछ समय पहले मैनेजमेंट ने ऐसे एक सांड को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका था (तब हमने इसकी चर्चा की थी)। जुलाई में ऐसे दूसरे सांड को भी आटोपिन मैनेजमेंट ने कान पकड़ कर निकाल दिया है।

वैसे, कोई मैनेजमेंट भी सर्व शक्तिमान नहीं है— हर मैनेजमेंट इस व्यवस्था की अन्धी शक्तियों द्वारा कठपुतली की तरह नचाई जाती है ? इसकी चर्चा अन्य स्थान पर करेंगे)।

ओलम्पिक

जोर-आजमाइश का अखाड़ा

अपनी शान और रौब के लिये राजे-रजवाड़े पहलवान भी पालते थे। रैय्या पहलवानों से खौफ खाती थी। पर राजा-जागीरदार के लिये अधिक महत्वपूर्ण था उसके पहलवानों द्वारा अन्य राजाओं-जागीरदारों के पहलवानों को पटकनी देना। यह उसकी शक्ति का एक प्रतीक था। मेलों आदि के खास मौकों पर अपने-अपने पहलवानों को राजा-जागीरदार अखाड़ों में उतारते थे। किसी पहलवान की हार का नतीजा आमतौर पर उसकी मौत होती थी— विरोधी पहलवान उसे मार नहीं डालता था तो उसका पालक उन्नीस हो जाने के गुस्से में पहलवान को मरवा देता था। यह सिर्फ भारत की विशेषता नहीं रही है, यूनान हो चाहे रोम यह एक सामान्य बर्बरता रही है।

समय बदला। राजे-रजवाड़े गये। राष्ट्रों-देशों का उदय हुआ। मेले विश्व मन्डी में विकसित हुये। पहलवानी अखाड़ों का स्थान ओलम्पिक ने लिया। मानवीय पहलू ने प्रगति की। इन हालात में पराजित पहलवान की हत्या-वध का स्थान हारने वाले खिलाड़ी की सार्वजनिक निन्दा ने लिया।

बिक्री के लिये उत्पादन के प्रसार ने खेलों व खिलाड़ियों को रूपये टके में तौलना तो शुरू किया ही, यह देशों की शक्ति-इज्जत के एक प्रतीक के तौर पर भी विकसित हुये। ओलम्पिक आज विश्व राजनीति में एक युद्ध है जिसमें हर देश के खिलाड़ी अपने अपने देश की तोप और गोला-बारूद हैं। हर खिलाड़ी के लिये ओलम्पिक पैसे व शोहरत का अखाड़ा है, खेलों से जड़े उद्योगों के लिये यह हिस्सा-पत्ती में बढ़ोतरी का एक बेहतरीन अवसर है, और हर देश के लिये अपने को इक्कीस साबित करने का एक माध्यम है।

खेलों से जुड़े उद्योग (रेडियो-टीवी-अखबार समेत) और हर देश की सरकार के हित माँग करते हैं कि वे दूसरों को पछाड़ने की कुत्सित भावना को हवा दें। इस सिलसिले में ऊँचे-नीचे, बड़े-छोटे, काले-गोरे, स्त्री-पुरुष अमीर-गरीब के विरासत में मिले भेदों को नये अर्थ व पैमाने दिये जाते हैं। निजी स्वार्थ-ईर्ष्या-निजी क्षमता को अलौकिक ऊँचाइयों की ओर धकेला जाता है। कोई खिलाड़ी हो, खेल उद्योग की कोई शाखा हो चाहें कोई सरकार हो, यह सब करना उनकी मजबूरी है। उनकी इस मजबूरी के लिये वास्तव में मानव समाज को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।

इस भारी कीमत चुकाने की एक अभिव्यक्ति खिलाड़ियों द्वारा वेतन वृद्धि और बेहतर वर्किंग कंडीशनों के लिये आम बनती जा रही हड़तालों के रूप में हो रही है तो दूसरी तरफ नये स्तर पर समस्या को समझने व समाधान के प्रयास भी नजर आने लगे हैं। टैनिस के एक प्रमुख खिलाड़ी बोरिस बेकर ने खेलों में जीत-जीत के लक्ष्य को हिटलरी जुनून करार दिया है। जर्मनी की टीम की तरफ से ओलम्पिक में हिस्सा लेने पहुँचे बोरिस बेकर ने एक सार्वजनिक बयान में यह कह कर कि वह जीतने नहीं बल्कि खेलने और दोस्त बनाने आया है, ओलम्पिक के ताम-झाँमी रहस्य में एक छेद कर दिया। इस पर जर्मनी में कुछ लोगों ये बोरिस बेकर के खिलाफ निन्दा अभियान चला कर उस जैसे विचारों को दबाने की कोशिश की है पर हो उल्टा रहा है और यह मानव समाज के लिये एक शुभ लक्षण है — जी०

पाठकों से

दुआ लफ्ज गड़बड़ है और मैटर प्रेस में देने के ऐन मौके पर दूसरा शब्द हमें सूझ नहीं रहा। क्या करें ? रिवाज है इसलिये चलो कह ही देते हैं कि आपकी दुआओं से यह पचासवाँ अंक निकल रहा है।

ऐसे मौकों पर थोड़ा रोना भी जरूरी होता है। कहेंगे कि पर्याप्त प्रतिक्रियायें हमें नहीं मिल रही हैं। टीका-टिप्पणियां नहीं भेजते हैं चलो कोई बात नहीं, यह हम खुद ही काफी कर लेते हैं। पर हाँ, मजदूर आन्दोलनों की अधिक रिपोर्टों की जरूरत है क्योंकि कहानियाँ बनाने में हम कुछ कमजोर हैं। रोचक निजी जीवनियों का तो अकाल ही पड़ा हुआ है, अव्वल न सही दूसरे दर्जे का मैटेरियल भी चलेगा। लेख का कन्सट्रक्शन कुछ झँझट वाला होता है इसलिये जो लोग माथा-पच्ची कुछ कम करना चाहते हैं वे खत ही लिखें पत्रों के रूप में सामग्री का स्वागत है !

काफी लोगों को हम बिन मांगे अखबार भेजते हैं। अप्रत्यक्ष अनिच्छा तो कई ने जताई है, इक्के-दुक्के ने डायरेक्ट भी कहा है। इस शुभ अवसर पर हम काम्पलीमेन्ट्री कापियों को कुतरने की सूचना दे रहे हैं। ज्यादा कागज चबाने से गड़बड़ का अन्देशा है इसलिये एक रिक्वेस्ट है : उन देवियों-सज्जनों के पते भेजें जो आपकी समझ अनुसार इस अखबार पर निगाह दौड़ाना चाहेंगे।

आखिरी कहिये चाहे अन्तिम कहिये, बात यह है: रूपये-टके-डालर का पृथ्वी से नामो-निशान मिटाने में जुटों को रूपये-टकों की जरूरत रहती है ..

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए उत्तरांचलप्रिन्टर्स, फरीदाबाद से मुद्रित